

गुणात्मक ताकत के रूप में फिनटेक*

शक्तिकांत दास

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (जीएफएफ) के तीसरे संस्करण में आज यहां आकर मुझे खुशी हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) और भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई) को बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम का विषय - एक संधारणीय वित्तीय विश्व का सृजन - वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है।

हाल के वर्षों में, भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में तेजी से प्रगति देखने को मिली है। प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और फिनटेक मिलकर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र की गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं। संधारणीय विकास और वित्तीय समावेशन के उच्च स्तर की दिशा में हमारी यात्रा में, ये ताकत गुणात्मक ताकत में बदल गए हैं। हमने इन ताकतों का काफी फायदा उठाया है; हमें और भी अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है।

अब मैं बारीकियों पर आता हूँ। भारत में प्रौद्योगिकीय सक्षमकर्ताओं की जबर्दस्त वृद्धि हुई है। दूरसंचार पैठ, इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता, क्रेडिट तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना, अधिक कुशल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और आगे भी प्रगति जारी है।

जुलाई 2022 के अंत में भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 80.7 करोड़ थी।¹ 46.5 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 134 करोड़ आधार नामांकन और 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन से सेवाओं के एकीकरण और उसे प्रदान करने के अभिनव तरीकों को लागू करने के नए अवसर खुल रहे हैं। इसका अंदाजा पिछले साल स्थापित रिकॉर्ड 44 यूनिर्कॉर्न के साथ देश में 100 यूनिर्कॉर्न के उभरने से लगाया जा सकता है²।

* 20 सितंबर 2022 को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, मुंबई में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का संबोधन।

¹ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

² पीआईबी प्रेस प्रकाशनी

तेजी से विकास करने के इच्छुक किसी भी समाज के लिए, उसके वित्तीय संस्थानों को मजबूत, सक्षम और सुलभ होना चाहिए। वित्त का अगला दशक दो केंद्रीय विषयों पर अधिक केंद्रित होगा: (i) संधारणीय विकास और (ii) प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष जो आम लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। इसलिए, संधारणीय विकास और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करना हमारी नीतिगत संरचना का आधार है।

जैसा कि हम सभी ने देखा है, विशेष रूप से दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 महामारी का सामना करने में प्रौद्योगिकी सुदृढ़ता का केंद्र रही है। यह संकट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और बहाली को संबल प्रदान करने में प्रमुख रहा है। वित्त के साथ-साथ प्रौद्योगिकी ने ऋणों के निर्बाध वितरण, मजबूत 24x7 भुगतान प्रणाली, वित्तीय बाजारों तक पहुंच, बीमा, एमएसएमई क्रेडिट, पेंशन सेवाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा की।

विश्व बैंक के अनुसार, विकासशील देशों में कम से कम 58 सरकारों ने कोविड-19 राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है³। इस संबंध में भारत में परिचालन का पैमाना निश्चित रूप से अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा था। ग्लोबल फिडेक्स डेटाबेस 2021⁴ ने दुनिया भर में वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विकासशील देशों में, 71 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं, जो एक दशक पहले 42 प्रतिशत से अधिक थे। अपने खाते से डिजिटल भुगतान करने (किसी व्यापारी या उपयोगिता सेवा के लिए) वालों में लगभग 40 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिन्होंने महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा किया।

भारत में, महामारी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की ओर जोर दिया। मार्च 2020 से अगस्त 2022 की अवधि में यूपीआई लेनदेन में 427 प्रतिशत की भारी वृद्धि

³ डिजिटल वित्तीय समावेशन पर कोविड-19 के प्रभाव संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

⁴ <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex>

देखी गई है, जो अकेले अगस्त 2022⁵ में 657 करोड़ लेनदेन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2022 के अंत तक यूपीआई क्यूआर कोड सक्षम भुगतान स्वीकार करने वाले केन्द्रों⁶ की संख्या लगभग 9 करोड़ ((86 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई, जो संपर्क रहित भुगतान के लिए बढ़ती स्वीकृति और प्राथमिकता को दर्शाता है।

हमारे वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष

भारत में वित्तीय सेवा उद्योग में भारी परिवर्तन देखा गया है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई, आधार ई-केवाईसी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस), क्यूआर स्कैन एंड पे, डिजिटल प्री-पेड इंस्ट्रुमेंट्स और इसी तरह की अन्य पहल जैसे उत्पादों ने पारंपरिक बैंकिंग परिचालन को बदल दिया है। बैंकिंग की समय अवधि बढ़ गयी है। अब हमारे पास डिजिटल-मोबाइल-कहीं भी-कभी भी बैंकिंग है। जहां कई पहलें उद्योग से उत्पन्न हुई हैं, वहीं सरकार और विनियामकों ने फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया स्टैक, अकाउंट एग्रीगेटर्स, पीयर टू पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म और 24x7 डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी पहलें प्रमुख समर्थक साबित हुई हैं। भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र वास्तव में विकसित हुआ है और एक ऊंचे छलांग के लिए तैयार है।

अब मैं इस क्षेत्र में आरबीआई द्वारा की गई कुछ अन्य पहलों के बारे में बात करना चाहूंगा। **विनियामकीय सैंडबॉक्स** फ्रेमवर्क को अगस्त 2019 में नवोन्मेष को बढ़ावा देने की दृष्टि से जारी किया गया था। इसके साथ, रिजर्व बैंक उन चुनिंदा समूह देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना स्वयं का विनियामकीय सैंडबॉक्स पारिस्थितिकी तंत्र है। खुदरा भुगतान, सीमा पार भुगतान, एमएसएमई उधार और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम पर चार थीम-आधारित कॉहोर्ट के बाद, इस महीने की शुरुआत में एक थीम न्यूट्रल फिफ्थ कोहोर्ट की घोषणा की गई थी। यह फिनटेक स्पेस में नवोन्मेष की उपस्थिति को बढ़ाने की हमारी तीव्र इच्छा को दर्शाता है। हमारी विनियामकीय सैंडबॉक्स पहल से निकलने वाली सफलता की कहानियों में अन्य बातों के अलावा,

⁵ एनपीसीआई वेबसाइट

⁶ भारतीय रिजर्व बैंक - भुगतान प्रणाली संकेतक (जुलाई 2022)

‘ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए फ्रेमवर्क’ और हाल ही में लॉन्च किया गया UPI123Pay शामिल है, जिसका उद्देश्य 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को संरक्षित और सुरक्षित तरीके से यूपीआई का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

रिजर्व बैंक ने पहली बार खुदरा भुगतान को और अधिक उन्नत बनाने के उद्देश्य से **हार्बिन्जर 2021 (HaRBinger 2021)** नामक एक वैश्विक हैकार्थॉन का आयोजन किया। इसमें उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। हमें 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें 22 विदेशों से थे जिनमें यूएसए और यूके जैसे देश शामिल थे। इस अभ्यास ने हमें रचनात्मक प्रतिभा पूल की एक झलक दी, जो भारत के पास है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि भारत फिनटेक स्पेस में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। मैं समझता हूं कि हार्बिन्जर 2021 (HaRBinger 2021) के विजेता भी अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए इस ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं।

हाल ही में, आरबीआई ने बंगलुरु में एक सहायक कंपनी के रूप में **रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)** की स्थापना की है। हब में निजी क्षेत्र और डोमेन विशेषज्ञों से लिए गए एक प्रतिष्ठित निदेशक मंडल हैं। आरबीआईएच वर्तमान में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर, आरबीआईएच खुद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बेंचमार्क बनाएगा।

हमने इस विकसित और गतिशील क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2022 से आरबीआई में एक नया फिनटेक विभाग भी बनाया है। इस विभाग का उद्देश्य न केवल नवोन्मेष को बढ़ावा देना है, बल्कि इससे जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करना भी है। अंतर-विनियामकीय मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अलावा वित्तीय क्षेत्र और बाजारों के लिए व्यापक प्रभाव वाले फिनटेक क्षेत्र में रचनात्मक नवोन्मेषों और अनुकूल वातावरण की सुविधा से संबंधित सभी मामलों को इस विभाग द्वारा निपटाया जा रहा है।

इसके अलावा, जैसा कि आप जानते होंगे, आरबीआई अब थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में **केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)** के चरणबद्ध कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से

काम कर रहा है। इससे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

फिनटेक; आगे का रास्ता

यह सर्वविदित है कि फिनटेक सेवा प्रदान करने के मामले में दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने में योगदान देता है। अपने अनुकूलित उत्पादों और ग्राहक इंटरफेस के माध्यम से, वे एक समृद्ध और निर्बाध उपभोक्ता अनुभव प्रदान करते हैं। पारंपरिक रूप से सेवा से वंचित या कम सेवा वाले सेगमेंट में ऋण और वित्तीय समावेशन तक पहुंच में सुधार के अलावा, उनके पास बाजार पहुंच और उत्पाद की पेशकश की एक श्रृंखला में सुधार करने की भी क्षमता है।

भारत में, फिनटेक द्वारा निभाई जा सकने वाली सबसे परिवर्तनकारी भूमिकाओं में से एक पारंपरिक उधारदाताओं के साथ साझेदारी में ऋण सुपुर्दगी का क्षेत्र है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। उचित लागत पर ऋण की समय पर उपलब्धता, विशेष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों और एमएसएमई के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इस तरह के ऋण का लाभ उठाने में वर्तमान में जुड़ी प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि यह प्रतिवर्तन समय के साथ बड़े पैमाने पर कागज आधारित प्रक्रिया है। कभी-कभी इसके लिए बैंक शाखाओं में बार-बार जाना पड़ता है और बोझिल दस्तावेज संबंधी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसमें उधारदाताओं के लिए उच्च परिचालन लागत और उधारकर्ताओं के लिए अवसर लागत शामिल है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और आरबीआई की फिनटेक पहलों को आगे बढ़ाते हुए, भारत में कृषि-वित्त के डिजिटलीकरण की परिकल्पना रिज़र्व बैंक और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के बीच की गई थी। यह विचार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों को कागज रहित और परेशानी मुक्त तरीके से प्रदान करने और टर्नअराउंड समय को कम करने एवं बैंक शाखाओं में बार-बार जाने से बचने के लिए था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब ने ग्रामीण ऋण तक निर्बाध और त्वरित पहुंच के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया तैयार की है। नए केसीसी ऋण और ऐसे ऋणों के नवीनीकरण के लिए एक सीमा तक (₹1.60 लाख) प्रति उधारकर्ताओं दोनों के

लिए इस नवोन्मेष पर आधारित एक प्रायोगिक परियोजना मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। आगे चलकर, प्रायोगिक परियोजना से मिली सीख के आधार पर, केसीसी ऋणों के डिजिटलीकरण को इन दोनों राज्यों के सभी जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है। आखिरकार, हमारी इच्छा ग्रामीण और कृषि ऋण पर विशेष जोर देने के साथ पूरे देश के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए घर्षण रहित ऋण की सुविधा हेतु एक एकीकृत और मानकीकृत प्रौद्योगिकीय मंच को विकसित और संचालित करना है। और अगर हम अगले एक वर्ष में ऐसा कर पाते हैं, तो यह भारत की विकास गाथा और भारत@2047 की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा।

आरबीआई द्वारा तकनीक-सक्षम विनियामकीय नवोन्मेष का एक अन्य उदाहरण अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क है। यह एक सुरक्षित और कुशल तरीके से संस्थानों में अपने वित्तीय डेटा को डिजिटल रूप से एक्सेस करने और साझा करने के लिए लाखों कम सेवा वाले ग्राहकों को सशक्त बनाने की क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित संस्थाओं को शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क का विस्तार किया गया है। यह ग्राहकों को अपने वित्तीय डेटा पर नियंत्रण हासिल करने और क्रेडिट, बीमा, निवेश सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयोग करने में मदद करने हेतु एक प्रगतिशील कदम है। केंद्रीकृत केवाईसी (सीकेवाईसी) और वीडियो केवाईसी डिजिटल और लागत प्रभावी तरीके से ग्राहकों की सहज ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए अन्य सक्षमकर्ता हैं। हम इन पहलों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

रिज़र्व बैंक सभी हितधारकों के समर्थन से ऐसी और पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में और हितधारकों के सहयोग से आज बाद में तीन रोमांचक नए उत्पाद लॉन्च किए जा रहे हैं। इनमें से दो 'यूपीआई लाइट' के माध्यम से छोटे मूल्य के लेन-देन की सुविधा और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़कर यूपीआई के फीचर सेट को बढ़ाने से संबंधित हैं। तीसरी पहल भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का उपयोग करके सीमा पार आवक बिल भुगतान को सक्षम बनाना है।

फिनटेक संस्थाओं के उद्भव और उनके अभिनव उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता ने वित्तीय सेवाओं में मौजूदा भागीदारों को अपने बाजार हिस्सेदारी, मार्जिन और ग्राहक आधार को बनाए रखने में चुनौती दी है। मौजूदा कंपनियां विभिन्न रणनीतियों को अपनाकर इन चुनौतियों का जवाब दे रही हैं, जिसमें फिनटेक कंपनियों में निवेश करना और उनके साथ साझेदारी करना शामिल है। वे नई वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं को भी बढ़ा रहे हैं।

फिनटेक द्वारा लाए गए कई परिवर्तनों का समावेशन बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं की और पैठ बनाने के मामले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही, इन घटनाक्रमों ने एक ऐसे युग की शुरुआत भी की है जहां भारी मात्रा में उपभोक्ता डेटा उत्पन्न किया जा रहा है और कुछ संस्थाओं (तथाकथित बिगटेक) द्वारा अपने विशाल ग्राहक आधार के बूते लाभ उठाया जा रहा है। इस तरह के घटनाक्रम संकेंद्रण जोखिम और संभावित स्पिलओवर संबंधी चिंता पैदा करते हैं क्योंकि वित्तीय प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव का स्तर आने वाले वर्षों में मजबूत होता है। इसलिए, प्रतिस्पर्धा, बाजार और व्यापार आचरण, परिचालन सुदृढ़ता, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों के लिए संभावित जोखिमों पर करीब से ध्यान देने की जरूरत है।

जैसा कि हमने देखा है, हाल के दिनों में जिस तरह से डिजिटल लेंडिंग ने रफ्तार पकड़ी है वह अभूतपूर्व था। जहां इसने विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया है, वहीं इसने कई चिंताओं को भी उजागर किया है जो कि ब्याज दरों, अनैतिक वसूली प्रथाओं और डेटा गोपनीयता की समस्याओं के बारे में शिकायतों के एक समूह के माध्यम से प्रकट हुई हैं। रिजर्व बैंक ने इन समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करने का प्रयास किया है और जून 2020 की शुरुआत में, हमारी विनियमित संस्थाओं को विनियामकीय दिशानिर्देश प्रदान किया गया था। इस दिशानिर्देश में, अन्य बातों के अलावा, अनिवार्य है कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म उन बैंकों/एनबीएफसी के नामों का खुलासा करें जिनकी ओर से वे ऋण प्रदान कर रहे थे। डिजिटल उधार⁷ पर हाल ही में

जारी विनियामक दिशानिर्देश एक तरफ ग्राहक संरक्षण और व्यापार आचरण और दूसरी तरफ नवोन्मेष का समर्थन करने के बीच एक सुविचारित संतुलन बनाते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जहां नवोन्मेषों का बहुत स्वागत है, वहीं उन्हें जिम्मेदार होना होगा और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हुए वित्तीय प्रणाली की दक्षता एवं सुदृढ़ता को बढ़ाना होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी अभिशासन के साथ मजबूत आंतरिक उत्पाद और सेवा आश्वासन ढांचे, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और फिनटेक संस्थाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। विनियमित संस्थाओं द्वारा उनकी आउटसोर्स की गई गतिविधियों पर उचित परिश्रम और निरीक्षण के स्तर को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे शुरुआती चरण में ही जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करने में मदद मिलेगी।

मैं डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के बेलगाम तेजी से बढ़ने के संबंध में कुछ भौतिक चिंताओं को भी चिह्नित करना चाहता हूँ। विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्रीन-लाइटिंग (श्वेतसूचीकरण) और उचित परिश्रम की प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुरक्षा का आश्वासन सुनिश्चित करना समय की मांग है। आरबीआई, अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर, इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठा रहा है तथा जरूरत पड़ने पर और कदम उठाएगा।

अभिशासन और आचरण

जहां हम प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवोन्मेष का समर्थन करना जारी रख रहे हैं, वहीं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभिशासन और आचरण के मुद्दों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। आखिरकार, किसी भी फिनटेक गतिविधि या कारोबार की स्थिरता ग्राहक सुरक्षा, बेहतर साइबर सुरक्षा तथा सुदृढ़ता, वित्तीय अखंडता का प्रबंधन और मजबूत डेटा सुरक्षा से संबंधित है।

⁷ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=54187; <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12382&Mode=0>

मैं फिनटेक समुदाय को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि आरबीआई नवोन्मेष को प्रोत्साहित और समर्थन देना जारी रखेगा। साथ ही, हम उम्मीद करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र अभिशासन, व्यापार आचरण, विनियामक अनुपालन और जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क पर ध्यान देगा। बड़ी संख्या में पहले से मौजूद मौजूदा संस्थाओं के अलावा आगे का फिनटेक रोड लगातार बढ़ते ट्रैफिक का गवाह बनेगा। इसलिए, यह जरूरी है कि इस सड़क पर चलने वाला प्रत्येक भागीदार अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करे।

निष्कर्ष

एक संधारणीय वित्तीय दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आरबीआई का ध्यान

हमेशा एक सुगम वातावरण प्रदान करके नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने पर रहा है। साथ ही, वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में, आरबीआई भी किसी भी अनुचित जोखिम बढ़ने के प्रति सतर्क रहता है और उस पर कार्रवाई करता है। मुझे यकीन है कि फिनटेक भागीदार इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ेंगे।

भारत में हमारे पास जो अद्भुत प्रतिभा आधार है और हाल के वर्षों में हमने डिजिटल एवं फिनटेक स्पेस में जो विशाल छलांग लगाई है, मुझे विश्वास है कि भारत इस क्षेत्र में भावी सोच को आकार देने के लिए अच्छी स्थिति में है। चूंकि हम एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हैं, इसलिए मैं आप सभी की आगे की सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।